Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies,
Online ISSN 2278-8808, SJIF 2021 = 7.380, www.srjis.com
PEER REVIEWED & REFEREED JOURNAL, MAR-APR, 2022, VOL- 9/70

भारत में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का जीवन की सामाजिक–आर्थिक गुणवत्ता पर प्रभाव (उ0 प्र0 के जनपद मैनपुरी के विशेष संदर्भ में)

मीतेश कुमार यादव[1] & कुमार राजीव रंजन[2], Ph. D.
[1]शोधार्थी, डॉ बी0 आर0 आ0 वि0वि0 आगरा मैनपुरी
[2]एसो0 प्रोफेसर, समाजशास्त्र विभाग, श्रीचित्रगुप्त पी0 जी0 कॉलेज

Paper Received On: 25 APR 2022
Peer Reviewed On: 30 APR 2022
Published On: 1 MAY 2022

Abstract

ग्रामीण एवं निम्न वर्ग के जीवन की सामाजिक–आर्थिक गुणवत्ता में सुधार लाने के लिये भारत सरकार ने सम्पूर्ण राष्ट्र में विभिन्न योजनाओं का शुभारम्भ किया गया है। वर्ष 2018 में एम.एस.डी.आई. ने प्रधान मंत्री कौशल केन्द्र , पी.एम.के.वी.वाई. के अन्तर्गत कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए उद्योग मानकीकृत बुनियादी ढांचों के निर्माण के लिए बडे पैमाने पर ध्यान केन्द्रित किया। प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बहुमुखी विकास (शिक्षा, रोजगार, कृषि, निर्धनता, स्वच्छता, स्वास्थ्य) एवं जीवन की गुणवत्ता सुधार के लिए भी इन योजनाओं का आशातीत सहयोग रहा है। सरकारी विकास योजनायें; निर्बल वर्ग के जीवन की गुणवत्ता एवं शिक्षित बेरोजगारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सहायक हैं।

पारिभाषिक शब्दावलीः *विकास कार्यक्रम, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, जीवन–गुणवत्ता, उद्यमिता।*

Scholarly Research Journal's is licensed Based on a work at www.srjis.com

शोध पद्धति : शोध की प्रकृति एवं अध्ययन के उद्देश्यों की दृष्टि से अन्वेषणात्मकत्मक शोध अभिकल्प को चुना गया है। उद्देश्य पूर्ति हेतु 100 निदर्शितों का चयन जनपद मैनपुरी (उ0 प्र0) से किया गया है।

उद्देश्यः प्रस्तुत शोध कार्य का मूल उद्देश्य विभिन्न योजनाओं गुणवत्ता एवं सार्थकता का परीक्षण करना है।

विश्लेषण एवं परिलब्धियाँ

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से ग्रामविकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत ऐसी मेल–मिलाप वाली योजनायें हैं, जो ग्रामीण आर्थिक एवं

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

सामाजिक जीवन को प्रभावित करती हैं। ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बहुमुखी विकास (शिक्षा, रोजगार, कृषि, निर्धनता, स्वच्छता, स्वास्थ्य) के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास किया जाता रहा है। इस विकास की प्रक्रिया में लोगों की भागीदारी, स्थानीय कौशल व संसाधनों को शामिल किया गया है। ग्रामीण–विकास के अन्तर्गत मुख्यतः कमजोर एवं उपेक्षित तबके पर विशेष ध्यान देते हुए स्थायी विकास के बहुत से कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं। शहरों में बसे लोग भी प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से गाँव से सम्बन्धित होते हैं। भारत को शक्तिशाली व समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी है कि गाँव गरीबी व पिछड़ेपन से मुक्त हो। गाँवों के उत्थान व विकास के लिए ही ग्रामीण विकास योजनायें प्रारम्भ की गई हैं।

ग्रामीण विकास एवं जीवन की गुणवत्ता के सुधार के लिए सरकारों द्वारा अपनाये गये कुछ प्रमुख संचालित परियोजनायें व कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

1. प्रधानमंत्री किसान सम्माननिधि योजना।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम।
3. स्वर्णजयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना।
4. इन्दिरा आवास योजना।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन।
6. प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना।
7. जवाहर रोजगार योजना।
8. ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम।
9. प्रधानमंत्री आवास योजना।
10. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। आदि

परिकल्पना

(1) योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हुए हैं।

(2) संचालित योजनाओं के प्रभाव से जीवन की सामाजिक–आर्थिक गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हुए हैं।

विश्लेषणः विकास योजनायें ग्रामीण एवं निम्न वर्ग के जीवन एवं शिक्षित बेरोजगारों के लिए लाभकारी ही नहीं है, बल्कि सामाजिक आर्थिक दृष्टि से

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

राष्ट्रीय विकास में योगदान को बढ़ाने में भी सहायक सिद्ध हुई हैं। निम्न तालिका (1) इस सम्बन्ध में निदर्शितों के अभिमतों पर प्रकाश डालती है –
तालिका (1) : ''सरकारी विकास योजनायें; निर्बल वर्ग के जीवन की गुणवत्ता एवं शिक्षित बेरोजगारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सहायक है ?'' –सूचनादाताओं के अभिमत (गटमैन के द्विआयामी मनोवृत्ति मापक के आधार पर)

तालिका (1)

क्रमांक	**शिक्षित बेरोजगारी की समस्या पर प्रभाव**	**आवृत्तियाँ**	**प्रतिशत**
1	शिक्षित बेरोजगारी के उन्मूलन एवं स्वावलम्बन में योजना सहायक है। **(हाँ)**	84	84.00
2	शिक्षित बेरोजगारी के उन्मूलन एवं स्वावलम्बन में योजना सहायक नहीं है। **(नहीं)**	16	16.00
	योग	100	100.00

प्रस्तुत तालिका के विश्लेषण से स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षित कुल 100 लाभार्थियों में से 84.00 प्रतिशत लाभार्थियों ने स्वीकार किया है कि सरकारी योजनायें **''शिक्षित बेरोजगारों की समस्या''** के समाधान एवं ग्रामीण सामाजिक आर्थिक गुणवत्ता सुधार में सहायक हैं; जब कि मात्र 16.00 प्रतिशत लाभान्वितों के अभिमत नकारात्मक रहे हैं। इन प्राथमिक तथ्यों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि **'' सरकारी विकास योजनायें; निर्बल वर्ग के जीवन की गुणवत्ता एवं शिक्षित बेरोजगारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान में सहायक सिद्ध हुई हैं।** ग्रामीण विकास के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के बहुमुखी विकास (शिक्षा, रोजगार, कृषि, निर्धनता, स्वच्छता, स्वास्थ्य) एवं जीवन की गुणवत्ता सुधार के लिए भी इन योजनाओं का आशातीत सहयोग रहा है।''

तालिका (2) : ''क्या सरकारी योजनायें ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, निर्धनता–उन्मूलन एवं आर्थिक स्वावलम्बन के साथ जीवन की गुणवत्ता के उत्थान में भी सहायक है ?'' सूचनादाताओं के अभिमत –

तालिका (2)

क्रमांक	सूचनादाताओं के अभिमत	आवृत्तियाँ	प्रतिशत
1	हाँ	81	81.00
2	नहीं	08	08.00
3	उदासीन	11	11.00
	योग	100	100.00

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

निम्न आगामी तालिका (3) के आंकड़ों की साँख्यकीय गणना करने पर χ^2 (Chi-Square value) , **0.782** प्राप्त होता है; जो कि स्वातंत्र्य कोटि–2 एवं पी0 मान (p- value)–5 प्रतिशत (0.05) के लिये χ^2 के निर्धारित मान 5.991 से अत्यन्त कम है। अतः **परिकल्पना को निरस्त नहीं किया जा सकता है।** उपरोक्त परिकल्पना के सत्यापन के लिये तालिका के प्राथमिक तथ्यों को भी दृष्टिगत रखा गया है। **परिकल्पना – ''सरकारी योजनायें भारतीय ग्रामीण नागरिकों के विकास, निर्धनता–उन्मूलन एवं आर्थिक स्वावलम्बन के साथ जीवन की गुणवत्ता के उत्थान में भी सहायक है''** सत्य एवं सार्थक पायी गई है।

तालिका (3)

	लिंग	हाँ	नहीं	योग(χ^2)
F_0	पुरूष	45	5	0.661
F_e		43	7	
$F_0 - F_e$		02	2	
$(F_0 - F_e)^2/F_e$		0.093	0.571	
F_0	महिला	41	09	0.661
F_e		43	07	
$F_0 - F_e$		02	2	
$(F_0 - F_e)^2/F_e$		0.093	0.571	
		(Chi-Square value) χ^2	स्वातंत्र्य कोटि – 2 पी0 मान – 5 प्रतिशत (0.05) के लिये निर्धारित χ^2 मान 5.991	1.322

निष्कर्षः इन समस्त प्राथमिक तथ्यों के आलोक में प्राप्त निष्कर्ष निम्नवत है–

(1) **'सरकारी योजनायें'** निर्धनता की सीमा–रेखा के अन्तर्गत जीवनयापन करने वाले निर्बल वर्गों के सामाजिक–आर्थिक विकास में सहायक है।

(2) **'कौशल विकास योजना'**, अतिरिक्त रोजगार के साधन सृजित करने वाले निर्धन परिवार; दैनिक आय में वृद्धि हो जाने के कारण ''निर्धनता की सीमा–रेखा'' पार करने में सक्षम हुए हैं। ऐसा होने से उनमें आत्म विश्वास जागा है। इस प्रकार यह योजना निर्बल वर्गों के विकासोन्मुख रचनात्मक भूमिका निभा रही है।

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies

(3) राष्ट्रीयकृत बैंकों के योगदान से, योजनान्तर्गत ऋण लाभांश (अनुदान तथा किस्तों में) प्रदान करके निर्धन परिवारों में लघु व कुटीर उद्योग धन्धों को स्वरोजगार के रूप में स्थापित करने एवं विकास हेतु संसाधन सुलभ कराने में सहायक सिद्ध हो रही हैं।

(4) सरकार द्वारा संचालित योजनायें, ग्रामीण निर्धनता व बेरोजगारी उन्मूलन में सहायक सिद्ध हो रही है।

(5) राष्ट्रीयकृत बैंकों ने रोजगारों की स्थापनाओं के लिए बिना प्रत्याभूति के, ऋण अनुदान पर प्रदान करके निर्धनता की सीमारेखा के नीचे जीवन जी रहे लोगों में स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना के प्रति जागरूकता एवं रूझान पैदा किया है इसलिए सहभागिता में वृद्धि हो रही है।

(6) सरकारी योजनाओं का ''समूहगत दृष्टिकोण'' लघु तथा कुटीर उद्योग धन्धों सम्बन्धी उद्यमों की स्थापनाओं एवं रोजगार के अतिरिक्त संसाधनों के सृजन में सहायक व सकारात्मक भूमिका का निर्वाह कर रहा है।

(7) योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वित परिवार आर्थिक दृष्टि से स्वावलम्बी हुए हैं।

(8) संचालित योजनाओं के प्रभाव से जीवन की सामाजिक–आर्थिक गुणवत्ता में सुधार परिलक्षित हुए हैं।

संदर्भ

महापात्र इन्द्रभूषण(2009) ; भारत के शिक्षित युवा चौराहे पर, 'राष्ट्रीय सहारा' समाचार पत्र, दिल्ली प्रकाशन, 30 जुलाई 1989

Verma P. (2003) ; Unemployment : Some Policy Issues, Himalaya Publications, Bombay, p. 14.

सोनी वर्षा (2002) ; ग्रमीण विकास – समस्या एवं समाधान, 'सामाजिक विमर्श' राष्ट्रीय शोध पत्रिका, मराठवाड़ा वि0वि0, पृष्ठ 102

..... (2002) ; 'आत्म निर्भर भारत', रिपोर्ट भारत सरकार नई दिल्ली, 2002, पृष्ठांकन– 53–54.

SHARMA SUBODH (2010) ; Contemporary Indian Social Problems, College Book Depot (Raj.) Jaipur, p. 206.

Chaudhary S. (2003) ;Educated Unemployment in India, Jyoti Publications (Pvt. Ltd.), Andheri West, Bombay, p. 63.

जैन पी0 के0 (2003) ; ग्रामीण युवा वर्ग में शिक्षित बेरोजगारी की समस्या 'अनुसंधानिका' शोध पत्रिका, गाजियाबाद, पृष्ठ 112

मिश्रा रूद्दत्त (2010) ; नौकरी नहीं उद्यमिता, हस्तक्षेप डैस्क (पत्रिका) जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली, 30 सितम्बर 2010, पृष्ठ 17

Copyright © 2022, Scholarly Research Journal for Interdisciplinary Studies